नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 197
दि. 21.04.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

महिला आरक्षण पर सियासी घमासान: आरोप-प्रत्यारोप के बीच बहस की खुली चुनौती, सड़कों से संसद तक तेज हुआ संघर्ष

(जीएनएस)। मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में महिला आरक्षण का मुद्दा अब केवल एक विधायी बहस नहीं रह गया है, बल्कि यह सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई का रूप ले चुका है। एक ओर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मुद्दे को महिला सशक्तिकरण की ऐतिहासिक पहल बताते हुए विपक्ष पर तीखे हमले कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की सांसद सुप्रिया सुले ने इस पूरे विमर्श को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाते हुए खुली बहस की चुनौती दे दी है। इस टकराव ने न केवल राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में महिला आरक्षण का मुद्दा चुनावी एजेंडे के केंद्र में रहने वाला है।

सोमवार को मुंबई में आयोजित एक प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी दलों पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि महिला आरक्षण का विरोध करना देश की करोड़ों महिलाओं के अधिकारों का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल लंबे समय से महिलाओं के सशक्तिकरण के खिलाफ मानसिकता रखते आए हैं और अब भी उसी सोच के तहत इस ऐतिहासिक विधेयक का विरोध कर रहे हैं। फडणवीस ने घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी राज्यभर में एक व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत एक करोड़ महिलाओं के हस्ताक्षर एकत्र किए जाएंगे। उनका कहना था कि यह अभियान केवल समर्थन जुटाने का माध्यम नहीं होगा, बल्कि यह महिलाओं की आवाज को मजबूती देने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का भी प्रयास होगा।

मुख्यमंत्री ने अपने बयान में यह भी कहा कि भाजपा इस मुद्दे को गांव-गांव और शहर-शहर तक लेकर जाएगी, ताकि हर महिला को यह समझाया जा सके कि यह विधेयक उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने की दिशा में कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में यह जनसमर्थन विपक्ष को अपने रुख पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर देगा। फडणवीस ने यहां तक कहा कि 2029 तक महिला आरक्षण का पूर्ण क्रियान्वयन संभव है और यह देश की राजनीतिक संरचना में एक बड़ा बदलाव लाएगा।

हालांकि, मुख्यमंत्री के इन बयानों के तुरंत बाद विपक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। सुप्रिया सुले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि महिला आरक्षण जैसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहा कि वे इस विषय पर कहीं भी, कभी भी खुली बहस के लिए तैयार हैं। सुले ने यह भी संकेत दिया कि मुख्यमंत्री पर केंद्र से दबाव हो सकता है, जिसके कारण वे इस मुद्दे को एकतरफा तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं।

सुप्रिया सुले ने अपने बयान में एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाया कि जब महिला आरक्षण विधेयक 2023 में संसद द्वारा पारित हो चुका है और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है, तो फिर इसके क्रियान्वयन में देरी क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि डिलिमिटेशन प्रक्रिया और महिला आरक्षण के लागू होने के बीच क्या संबंध है, और आखिर क्यों इसे तत्काल लागू नहीं किया जा रहा। उनके इस सवाल ने पूरे विवाद को एक नई दिशा दे दी है, जहां अब बहस केवल समर्थन और विरोध तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसके क्रियान्वयन की समयसीमा और प्रक्रिया पर भी केंद्रित हो गई है।

इसी बीच, शिवसेना (शिंदे गुट) ने भी इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाते हुए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष एक तरफ महिला आरक्षण का समर्थन करने का दावा करता है, जबकि दूसरी तरफ राजनीतिक कारणों से इसके रास्ते में बाधाएं खड़ी करता है। उनके अनुसार, यह व्यवहार महिलाओं की भावनाओं के साथ सीधा विश्वासघात है।

वर्सोवा में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। शिवसेना नेताओं का कहना था कि उनकी पार्टी हमेशा महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के लिए खड़ी रही है और भविष्य में भी इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस प्रदर्शन ने यह संकेत दिया कि महिला आरक्षण का मुद्दा अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनआंदोलन का रूप भी ले सकता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिला आरक्षण को लेकर यह टकराव आने वाले चुनावों में एक प्रमुख मुद्दा बन सकता है। एक ओर जहां सत्तापक्ष इसे महिला सशक्तिकरण के एजेंडे के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, वहीं विपक्ष इसके क्रियान्वयन में हो रही देरी और राजनीतिक मंशा पर सवाल उठा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महिला आरक्षण का मुद्दा केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन और राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी उतनी ही आवश्यकता है।

महाराष्ट्र की सियासत में इस समय जो माहौल बना हुआ है, वह आने वाले दिनों में और अधिक तीखा हो सकता है। बयानबाजी, आरोप-प्रत्यारोप और सार्वजनिक प्रदर्शन इस बात का संकेत हैं कि यह मुद्दा अभी लंबे समय तक राजनीतिक विमर्श के केंद्र में बना रहेगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह बहस किसी ठोस समाधान की ओर बढ़ेगी या फिर यह केवल राजनीतिक लाभ-हानि के समीकरण तक ही सीमित रह जाएगी।

फ्रीबीज बहस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख स्पष्ट, नई याचिका खारिज कर कहा—मामला पहले से विचाराधीन

(जीएनएस)। नई दिल्ली में चुनावी राजनीति के सबसे विवादित मुद्दों में से एक—'फ्रीबीज' यानी मुफ्त योजनाओं—पर एक अहम न्यायिक घटनाक्रम सामने आया है। Supreme Court of India ने चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाओं के वादों पर रोक लगाने की मांग वाली एक नई याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि इस विषय से जुड़े कई मामले पहले से ही उसके समक्ष लंबित हैं, इसलिए समान प्रकृति की नई याचिका पर अलग से सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब देश में चुनावी घोषणापत्रों में किए जाने वाले वादों को लेकर बहस तेज है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि राजनीतिक दलों द्वारा सरकारी संसाधनों के आधार पर मुफ्त सुविधाओं का वादा करना न केवल वित्तीय अनुशासन के खिलाफ है, बल्कि यह मतदाताओं को प्रभावित करने का एक माध्यम भी बन सकता है। याचिका में इसे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए खतरा बताते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की गई थी। याचिका में यह भी कहा गया था कि इस तरह के वादों को 'भ्रष्ट आचरण' की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ ही, Election Commission of India को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह ऐसे वादों पर सख्ती से रोक लगाए और उल्लंघन करने वाले दलों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करे।

एक और महत्वपूर्ण सुझाव यह दिया गया था कि राजनीतिक दलों को अपने घोषणापत्र में यह स्पष्ट करना चाहिए कि जिन मुफ्त योजनाओं का वे वादा कर रहे हैं, उनके लिए वित्तीय संसाधन कहाँ से आएंगे। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि मतदाता भी यह समझ पाएंगे कि ये वादे कितने व्यवहारिक और टिकाऊ हैं।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका के गुण-दोष पर कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं की, बल्कि प्रक्रिया के आधार पर इसे खारिज किया। अदालत का कहना था कि चूंकि इस विषय पर पहले से ही व्यापक सुनवाई चल रही है, इसलिए नई याचिका पर अलग से विचार करना न्यायिक समय और संसाधनों का उचित उपयोग नहीं होगा।

यह निर्णय अपने आप में यह संकेत देता है कि 'फ्रीबीज' का मुद्दा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि यह न्यायिक समीक्षा के दायरे में बना हुआ है। पहले से लंबित याचिकाओं में इस विषय के विभिन्न पहलुओं—आर्थिक प्रभाव, संवैधानिक वैधता और चुनावी निष्पक्षता—पर विस्तार से विचार किया जा रहा है।

देश में 'फ्रीबीज' की राजनीति लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। कुछ लोग इसे कल्याणकारी योजनाओं का हिस्सा मानते हैं, जो गरीब और वंचित वर्गों को राहत देती हैं, जबकि अन्य इसे राजकोषीय अनुशासन के लिए खतरा और चुनावी लाभ पाने का साधन बताते हैं। इस बहस में यह सवाल भी बार-बार उठता है कि सरकार की जिम्मेदारी और राजनीतिक लाभ के बीच की रेखा कहाँ खींची जाए।

सुप्रीम कोर्ट का यह रुख इस बात को भी रेखांकित करता है कि ऐसे जटिल मुद्दों पर जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय व्यापक और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जो भी फैसला हो, वह सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए और दीर्घकालिक प्रभावों को समझते हुए लिया जाए।

फिलहाल, इस नई याचिका के खारिज होने के बावजूद 'फ्रीबीज' पर बहस जारी रहेगी। अब निगाहें उन लंबित मामलों पर टिकी हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट भविष्य में कोई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश या फैसला दे सकता है। यह फैसला न केवल चुनावी राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि देश की आर्थिक नीतियों और शासन प्रणाली पर भी दूरगामी असर डाल सकता है।

विजय के हलफनामों में करोड़ों का फर्क, हाईकोर्ट की सख्ती ने बढ़ाई चुनावी गर्मी

(जीएनएस)। Chennai में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है। चर्चित अभिनेता और राजनीतिक चेहरा Vijay अब अपने चुनावी हलफनामों को लेकर विवादों में घिर गए हैं। Madras High Court ने उनके खिलाफ दायर याचिका पर संज्ञान लेते हुए उन्हें, Election Commission of India और Income Tax Department को नोटिस जारी किया है। यह मामला उस समय सामने आया, जब चुनावी हलफनामों में संपत्ति के ब्योरे को लेकर कथित विसंगतियों का आरोप लगाया गया। याचिकाकर्ता वी. विग्नेश ने अदालत में दावा किया कि विजय द्वारा अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से दाखिल किए गए फॉर्म 26 हलफनामों में संपत्ति के आंकड़े मेल नहीं खाते। याचिका के अनुसार, Tiruchirappalli East निर्वाचन क्षेत्र से दाखिल हलफनामे में विजय की चल संपत्ति 224 करोड़ रुपये बताई गई है, जबकि Perambur से दाखिल दूसरे हलफनामे में यह आंकड़ा केवल 105 करोड़ रुपये दर्शाया गया। दोनों ब्योरे के बीच 100 करोड़ रुपये से अधिक का अंतर सामने आने के बाद यह मामला गंभीर बन गया है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि इतनी बड़ी राशि का अंतर बिना किसी स्पष्ट स्पष्टीकरण के दर्शाया जाना न केवल संदिग्ध है, बल्कि यह चुनावी पारदर्शिता के नियमों के खिलाफ भी हो सकता है। उन्होंने अदालत से मांग की है कि इस मामले की विस्तृत जांच कराई जाए और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाए।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने भी इस अंतर को गंभीरता से लिया। मौखिक टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि इतनी बड़ी वित्तीय भिन्नता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और यह एक संभावित अनियमितता की ओर इशारा करता है। यही कारण है कि अदालत ने संबंधित सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

इस घटनाक्रम ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे को फिर से केंद्र में ला दिया है। चुनावी हलफनामे किसी भी उम्मीदवार की वित्तीय स्थिति और पृष्ठभूमि को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। ऐसे में यदि इन दस्तावेजों में विरोधाभास सामने आता है, तो यह मतदाताओं के भरोसे को प्रभावित कर सकता है।

विजय, जो इस चुनाव में एक प्रमुख और चर्चित चेहरा बने हुए हैं, उनके लिए यह विवाद राजनीतिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। उनके समर्थकों के बीच जहां इस मामले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वहीं विपक्षी दल इसे एक बड़े मुद्दे के रूप में उठा सकते हैं।

अब इस मामले की अगली सुनवाई प्रतिवादियों के जवाब दाखिल करने के बाद होगी। अदालत के समक्ष यह स्पष्ट करना होगा कि दोनों हलफनामों में संपत्ति के आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर क्यों है और क्या यह केवल तकनीकी गलती है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है।

फिलहाल, यह मामला चुनावी माहौल में एक नई बहस को जन्म दे चुका है—क्या उम्मीदवार अपने हलफनामों में पूरी पारदर्शिता बरत रहे हैं? और यदि नहीं, तो ऐसी स्थिति में कानून किस तरह सख्ती से लागू किया जाना चाहिए? आने वाले दिनों में इस मामले की दिशा और अदालत का रुख चुनावी राजनीति पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है।

होर्मुज में टकराव से कूटनीति पर छाया संकट, ईरान-अमेरिका वार्ता अनिश्चित

(जीएनएस)। मध्य पूर्व के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में गिने जाने वाले Strait of Hormuz में हालिया घटनाक्रम ने क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। Iran और United States के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध इस घटना के बाद और अधिक जटिल हो गए हैं। अमेरिकी नौसेना द्वारा ईरानी झंडे वाले एक मालवाहक पोत को रोककर जब्त किए जाने की कार्रवाई ने न केवल सैन्य स्तर पर तनाव बढ़ाया है, बल्कि दोनों देशों के बीच संभावित वार्ता की दिशा को भी धुंधला कर दिया है। यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संपर्कों को फिर से शुरू करने की संभावना पर चर्चा चल रही थी। लेकिन समुद्र में हुई इस कार्रवाई ने भरोसे के उस नाजुक ताने-बाने को झटका दिया है, जिस पर किसी भी बातचीत की नींव टिकती है। अमेरिका का कहना है कि संबंधित पोत उसकी नाकेबंदी से बचने की कोशिश कर रहा था, जबकि ईरान ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताते हुए 'लूटमार' जैसी कठोर संज्ञा दी है। घटना के विवरण के अनुसार, अमेरिकी नौसेना के एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक ने 'तूस्का' नामक पोत को रोककर अपने नियंत्रण में लिया और उसकी तलाशी ली। इस दौरान पोत की गतिविधियों और उसमें मौजूद सामान की जांच की गई। हालांकि, यह केवल एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं थी, बल्कि इसके राजनीतिक और कूटनीतिक निहितार्थ कहीं अधिक व्यापक हैं। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए जवाबी कदम उठाने की चेतावनी दी है। हालांकि तत्काल प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत सीमित रही, जिसके पीछे मानवीय कारण बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, पोत पर चालक दल के साथ उनके परिजन भी मौजूद थे, जिनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ईरान ने त्वरित सैन्य प्रतिक्रिया से परहेज किया। यह पहलू इस पूरे घटनाक्रम को और संवेदनशील बना देता है, क्योंकि इसमें केवल रणनीतिक हित ही नहीं, बल्कि मानवीय चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं।

इस टकराव का सबसे बड़ा असर कूटनीतिक मोर्चे पर देखने को मिल रहा है। Abbas Araghchi ने अमेरिकी कदम को वार्ता से पहले की 'गैर-ईमानदार मंशा' करार दिया है। उनका कहना है कि जब एक पक्ष बातचीत की बात करता है और दूसरी ओर ऐसी सैन्य कार्रवाई करता है, तो यह विश्वास निर्माण की प्रक्रिया को कमजोर करता है।

इस बीच, Pakistan ने इस बढ़ते तनाव के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इस्लामाबाद ने वॉशिंगटन और तेहरान दोनों से संपर्क बढ़ाया है, ताकि संभावित वार्ता को फिर से पटरी पर लाया जा सके। पाकिस्तान की यह सक्रियता इस बात का संकेत है कि क्षेत्रीय देश भी इस टकराव के व्यापक प्रभावों को लेकर चिंतित हैं और किसी बड़े संघर्ष को टालने के प्रयास में जुटे हैं।

होर्मुज जलडमरूमध्य का महत्व केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक है। यह मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन रास्तों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचता है। ऐसे में यहां किसी भी प्रकार का तनाव वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों पर सीधा असर डाल सकता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में होने वाली हर गतिविधि पर पूरी दुनिया की नजर रहती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना ने दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद अविश्वास को और गहरा कर दिया है। ऐसे में निकट भविष्य में किसी ठोस वार्ता की संभावना कम होती दिखाई दे रही है। हालांकि कूटनीति में परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं, लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं, वे अनिश्चितता की ओर इशारा करते हैं। यह घटनाक्रम यह भी दर्शाता है कि सैन्य और कूटनीतिक रणनीतियों के बीच संतुलन बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। एक ओर सुरक्षा और रणनीतिक हितों की रक्षा जरूरी होती है, वहीं दूसरी ओर संवाद और विश्वास निर्माण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जब इनमें संतुलन बिगड़ता है, तो तनाव बढ़ना स्वाभाविक है।

फिलहाल, होर्मुज में बढ़ते तनाव ने पूरे क्षेत्र को सतर्क कर दिया है। दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में ईरान किस तरह की प्रतिक्रिया देता है और क्या अमेरिका अपनी रणनीति में कोई बदलाव करता है। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि क्या कूटनीतिक प्रयास इस तनाव को कम करने में सफल हो पाते हैं या फिर यह टकराव किसी बड़े संकट का रूप ले लेता है।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

नैतिकता अनुरूप हो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग

आज का समय मानव इतिहास के सबसे परिवर्तनकारी दौरों में से एक माना जा रहा है, जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ने हमारी सोच, कार्यशैली और सामाजिक संरचनाओं को गहराई से प्रभावित करना शुरू कर दिया है। एक ओर यह तकनीक अभूतपूर्व गति, दक्षता और नवाचार का माध्यम बनी है, वहीं दूसरी ओर इसके बढ़ते प्रभाव को लेकर वैश्विक स्तर पर गंभीर चिंताएँ भी उभर रही हैं। समाज के बुद्धिजीवी, आध्यात्मिक गुरु और सामाजिक चिंतक लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यदि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास और उपयोग नैतिक मूल्यों के अनुरूप नहीं हुआ, तो इसके परिणाम मानवता के लिए घातक हो सकते हैं। इसी संदर्भ में Pope Leo XIV की हालिया चेतावनी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने आशंका जताई कि एआई वैश्विक ध्रुवीकरण, संघर्ष, भय और हिंसा को बढ़ावा दे सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मूल स्वभाव तटस्थ माना जाता है, लेकिन वास्तव में यह पूरी तरह निष्पक्ष नहीं है। इसे बनाने वाले मनुष्य अपने विचार, पूर्वाग्रह और उद्देश्यों को इसमें कहीं न कहीं शामिल कर देते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि एआई का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि इसे किस तरह डिजाइन किया गया है और किन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है। यदि इसका उपयोग जनकल्याण के लिए किया जाए तो यह वरदान सिद्ध हो सकती है, लेकिन यदि इसे सत्ता, नियंत्रण या मुनाफे के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो इसके दुष्परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। हाल के वर्षों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में एआई के दुरुपयोग के कई उदाहरण सामने आए हैं। चुनावों के दौरान डीपफेक वीडियो और क्लोन की गई आवाजों का उपयोग करके झूठी सूचनाएँ फैलाई गईं, जिससे मतदाताओं को भ्रमित किया गया। इस तरह की घटनाएँ न केवल लोकतंत्र की पारदर्शिता को प्रभावित करती हैं, बल्कि जनता के विश्वास को भी कमजोर करती हैं। जब नागरिकों को यह भरोसा ही न रहे कि वे जो देख और सुन रहे हैं वह वास्तविक है या नहीं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव ही हिलने लगती है। साइबर अपराध के क्षेत्र में भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने एक नई चुनौती प्रस्तुत की है। पहले जहाँ ठगी के लिए सीमित संसाधनों और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती थी, अब एआई के माध्यम से यह कार्य बेहद आसान और व्यापक हो गया है। आवाज की क्लोनिंग के जरिए अपराधी किसी व्यक्ति के परिचित बनकर संपर्क करते हैं और भावनात्मक दबाव बनाकर आर्थिक धोखाधड़ी करते हैं। इस प्रकार के अपराधों में लाखों लोग अपनी जीवन भर की कमाई गंवा चुके हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि तकनीक का दुरुपयोग किस हद तक खतरनाक हो सकता है। वित्तीय क्षेत्र में एआई का संभावित खतरा और भी गंभीर है। उन्नत एआई सिस्टम बैंकिंग नेटवर्क की कमजोरियों को पहचानकर स्वचालित हमले कर सकते हैं। इससे न केवल व्यक्तिगत खातों को नुकसान हो सकता है, बल्कि पूरी आर्थिक व्यवस्था अस्थिर हो सकती है। यदि भुगतान प्रणाली में बाधा आती है या बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी होती है, तो इससे वैश्विक स्तर पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। यही कारण है कि नियामक संस्थाओं के लिए एआई से उत्पन्न जोखिमों को समझना और उनका समाधान करना एक बड़ी चुनौती बन गया है।

राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी एआई का प्रभाव गहरा है। फर्जी समाचार, दुष्प्रचार और एल्गोरिदमिक पक्षपात के माध्यम से समाज में विभाजन पैदा किया जा सकता है। इससे विभिन्न समुदायों के बीच अविश्वास बढ़ता है और सामाजिक समरसता को नुकसान पहुँचता है। Pope Leo XIV ने इसी खतरे की ओर इशारा करते हुए कहा कि यदि एआई का उपयोग जिम्मेदारी से नहीं किया गया, तो यह मानवता को जोड़ने के बजाय तोड़ने का माध्यम बन सकता है। पर्यावरणीय दृष्टि से भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एआई सिस्टम को संचालित करने के लिए बड़े-बड़े डेटा सेंटरों की आवश्यकता होती है, जो भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत करते हैं। इसके अलावा, कोबाल्ट और लिथियम जैसे खनिजों की बढ़ती मांग ने खनन गतिविधियों को तेज कर दिया है, जिससे पर्यावरण को नुकसान और स्थानीय समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार, एआई का विकास केवल तकनीकी प्रगति का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक न्याय से भी जुड़ा हुआ मुद्दा बन गया है। हालांकि, इन सभी चुनौतियों के बावजूद कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सकारात्मक पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चिकित्सा क्षेत्र में यह बीमारियों के शीघ्र और सटीक निदान में मदद कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में यह व्यक्तिगत सीखने के अनुभव को बेहतर बना रही है। आपदा प्रबंधन में यह त्वरित निर्णय लेने और संसाधनों के प्रभावी उपयोग में सहायक सिद्ध हो रही है। इसलिए यह स्पष्ट है कि एआई को पूरी तरह नकारना न तो संभव है और न ही उचित। समाधान का रास्ता संतुलन और जिम्मेदारी में निहित है। सरकारों को चाहिए कि वे एआई के विकास और उपयोग के लिए सख्त और स्पष्ट नियम बनाएं। कंपनियों को अपने एल्गोरिदम में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि उपयोगकर्ता का विश्वास बना रहे।

संवादहीनता के चलते महिला आरक्षण पर गतिरोध

> "विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। दरअसल, इस बार नए विधेयक पर आम सहमति न तो चाही गई और न ही हासिल की गई क्योंकि इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में परस्पर बातचीत नहीं हुई। जबकि 2023 में कांग्रेस समेत विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम एकमत से पास कराने में भाजपा का साथ दिया था।

भारतीय राजनीति में 'महिला वोट बैंक' बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उल्लेखनीय परियोजना, जिसके जरिए वे जाति और वर्ग, दोनों की राजनीति को पछाड़ने की उम्मीद रखे हुए हैं, पिछले 12 सालों में वह कल्पनातीत रूप से काफी कारगर रही है। मोदी ने हाल के दिनों में किसी भी दूसरे पुरुष नेता से ज़्यादा महिलाओं की शिकायतें सुनने का प्रयास किया है- शुरुआत गांव के छोटे घरों में इस्तेमाल होने वाले, धुआं पैदा करने वाले चूल्हों को 'उज्ज्वला' स्कीम के तहत गैस सिलेंडर से बदलने की मुहिम से हुई, और फिर उनके बैंक खाते में पैसे डाले गए, खासकर उनके राज्यों में चुनावों से पहले।

तो फिर, महिला आरक्षण बिल, जिसे पेश करने की अगुवाई प्रधानमंत्री ने लोकसभा में की, यहां तक कि कुछ राज्यों में जारी चुनाव प्रचार के बीच में संसद का विशेष सत्र बुलाया, वह स्वीकृत क्यों नहीं हो पाया? क्या भारत की महिलाएं राष्ट्रीय 'नारी शक्ति' का हिस्सा नहीं बनना चाहतीं? इसका जवाब जटिल है, जाहिर है, शुरुआत इस तथ्य से होगी कि देवियों में हमारी गहरी आस्था के बावजूद, दुर्गा से लेकर काली, सरस्वती और लक्ष्मी और भी बहुत सारी, आप पूछ सकते हैं कि भारत में पुरुष-प्रधान समाज की जड़ें इतनी गहरी क्यों हैं। अवश्य ही, हम महिलाएं ही उन जड़ों को सींचने और अपना ही नुकसान करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। वरना हरियाणा में महिला-पुरुष अनुपात (879/1,000), पंजाब (895/1,000) व दिल्ली (868/1,000) न होता —मानें या न मानें, 1000 पुरुषों पर 818 महिलाओं के साथ चंडीगढ़ का आंकड़ा देशभर में सबसे नीचे है, राष्ट्रीय सूची में ये सब नीचे क्यों है? (हालांकि हरियाणा का दावा है कि पिछले साल उसका आंकड़ा बढ़कर प्रति 1,000 पुरुषों पर 914 महिलाएं हो गया है।)

सवाल उठता है कि केरल के बराबर आबादी वाला पंजाब, दोनों की आबादी लगभग 3 करोड़ है, लिंगानुपात के पैमाने पर देशभर में दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य क्यों है? केरल (1,084), तमिलनाडु (996), आंध्र प्रदेश और कर्नाटक (दोनों 993) जैसे दक्षिणी राज्यों का प्रदर्शन उत्तरी राज्यों की तुलना में इस पैमाने (और अन्य कई सामाजिक-आर्थिक मापदंडों पर भी) इतना बढ़िया क्यों है? दूसरा सवाल पूछना बनता है कि विपक्षी दल महिला आरक्षण बिल के खिलाफ क्यों हैं? उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लाए उस विधान का समर्थन क्यों नहीं किया, जिससे भारतीय राजनीति में उलटफेर होना तय है? क्या विपक्ष महिला विरोधी है?

पिछले कुछ दशकों में महिला आरक्षण कानून का सफर काफी लंबा रहा, जैसा कि मेरी सहयोगी सूर्या पिल्लई ने इस विषय पर कुछ दिन पहले बहुत बढ़िया लिखा था। सच तो यह है कि 2008 में कांग्रेस नीत यूपीए ने ही संसद में महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पेश किया था, और सुनिश्चित किया कि 2010 में पास हो जाए, राज्य सभा में भी, ताकि यह 'लैप्स' न हो (तय अवधि में पास होना अनिवार्य है, परंतु जब कोई कानून राज्यसभा में पास हो जाए, तब 'लैप्स' नहीं होता)। कांग्रेस को अहसास था कि महिला आरक्षण बिल पर उसकी अपनी यूपीए बंटी हुई है (आरजेडी नेता शरद यादव ने 'पर कटी महिलाएं' जैसा कटाक्ष किया था और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने तो यह तक कह डाला कि अगर संसद महिला आरक्षण कानून पास कर देगी तो यह उन महिलाओं के लिए दरवाज़े खोल देगा 'जिन पर फब्ती कसी जाती और सीटियां बजती हैं', ये बिल पर आपसी मतभेद दर्शाता है), जिसका मतलब था कि उसके पास अपने समय की लोकसभाओं में इसे पास करा लेने को कभी भी पर्याप्त संख्या नहीं रही, लिहाजा उन्होंने दूसरा बेहतर विकल्प चुना।

कांग्रेस के जोर देने पर मोदी सरकार ने 2023 में यह काम आगे बढ़ाया और सुधार करने के बाद कानून पास किया गया। इसीलिए 2023 में, कांग्रेस और बाकी विपक्ष ने, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को एकमत से पास कराने में भाजपा का साथ दिया।

और 2026 के बिल में भी यही संदेश मिलना चाहिए था- आम सहमति। जिस प्रकार 2023 में पूरी संसद इस मुद्दे पर सर्वसम्मत थी- केवल दो सांसदों ने बिल के ख़िलाफ़ वोट दिया था- संसद में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने के समर्थन में। इस बार प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और शेष वरिष्ठ भाजपा नेतृत्व को चाहिए था कि विपक्ष को बुलाकर महिला आरक्षण बिल पर उनका समर्थन मांगते। यह भी हो सकता था कि एक संयुक्त संसदीय समिति या कोई विशेष समिति, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि होते, इस कानून की तमाम धाराओं पर बारीकी से बहस करते -मसलन, क्या इसमें अन्य पिछड़ी जातियों और दलित महिलाओं के लिए 'कोटे के अंदर कोटा' होगा?- और एक बार आम सहमति बन जाने के बाद, नया कानून और उसे लागू करने की रूपरेखा को सदन में रखा जाता।

बदकिस्मती से, न तो आम सहमति बनानी चाही और न ही हासिल की जा सकी क्योंकि कोई संवाद नहीं हुआ। इन दिनों संसद इस कदर बंटी हुई है कि सांसद एक-दूसरे से अपमानजनक रूप से बोल रहे हैं, इसके लिए एक बड़े दिल वाले और छोटे अहम वाले नेता की ज़रूरत है, जो छोटी-मोटी बातों और चालबाजियों को भुलाकर दूसरे पक्ष से मेल-मिलाप रखे और संवाद करे।

साफ है, महिला आरक्षण बिल का भी वही हाल हुआ है जो 2020 में तीन कृषि कानूनों का हुआ था। ठीक वैसे ही जिस प्रकार केंद्र को तीनों कानून वापस लेने पड़े, क्योंकि उन्हें लाने से पहले किसान संगठनों और राजनीतिक दलों के साथ बहुत कम संवाद या चर्चा की गई थी -शायद पंजाब के एक हिस्से में बतौर पायलट प्रोजेक्ट इन कृषि कानूनों का प्रयोग किया जा सकता था, जिससे दोनों पक्षों को कोई राह मिल जाती- उसी तरह सत्ता पक्ष महिला आरक्षण कानून पास कराने लायक संख्या नहीं जुटा पाया। प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता से कह सकते थेः 'आइए मिलकर इतिहास लिखें। अब समय आ गया है कि महिलाएं कम से कम एक-तिहाई आसमान छूएं। यूं तो देश की कुल आबादी में महिलाओं की गिनती 48-49 प्रतिशत है, लेकिन शुरुआत के लिए, उन्हें 33 फीसदी देते हैं'। इसपर विपक्ष के नेता का जवाब होताः 'हां, चलिए, हम साथ हैं'। दुर्भाग्यवश, मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और के. कनिमोझी अपनी-अपनी दलीलें देते रहे। संसद किस हद तक बदल गयी है, यह तब साफ हो गया जब प्रियंका गांधी-अमित शाह की एक-दो टिप्पणियां– जिन्हें पुराने दिनों में संसदीय बहस में सलीके से बात काटने और हाजिर जवाबी का आम तरीका माना जाता था– इस पर कुछ सांसद हंसने लगे, कुछ तो घबराए से भी। सत्ता और विपक्ष के बीच संवाद की कमी से संसद में महिलाओं के मुद्दे पर टकराव हो गया।

एक और अहम बात यह कि शुक्रवार शाम को कानून में संवैधानिक संशोधन असफल रहने के 24 घंटे से भी कम समय पहले, सरकार ने गुरुवार देर शाम 2023 नारी शक्ति अधिनियम अधिसूचना जारी कर दी थी। इसका मतलब है कि कानून अभी सक्रिय है और इसे कभी भी लागू किया जा सकता है।

बिखराव के इस समय में, यह आखिरी प्रयास उम्मीद जगाता है।

प्रेरणा

निष्पक्ष भक्ति और अखंड समन्वय का जीवंत स्वर

भारतीय अध्यात्म की धरती पर समय-समय पर ऐसे दिव्य व्यक्तित्व अवतरित हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन के माध्यम से यह सिद्ध किया कि धर्म का वास्तविक स्वरूप सीमाओं में नहीं, बल्कि असीम व्यापकता में निहित है। ऐसे ही अद्वितीय संतस्वरूप व्यक्तित्व थे Hanuman Prasad Poddar, जिन्हें स्नेहपूर्वक 'भाई जी' कहा जाता है। उनका जीवन केवल व्यक्तिगत साधना का उदाहरण नहीं था, बल्कि वह समन्वय, निष्पक्षता और निस्वार्थ सेवा का एक जीवंत आदर्श था, जिसने लाखों लोगों के जीवन को दिशा प्रदान की।

भाई जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची आध्यात्मिकता किसी एक विचारधारा या संप्रदाय की सीमा में बंधकर नहीं रह सकती। उन्होंने अपने कार्यों और विचारों के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि सभी धार्मिक मार्ग अंततः एक ही परम सत्य की ओर ले जाते हैं। वे Gita Press Gorakhpur के संस्थापक थे, जिसने सनातन धर्म के ग्रंथों को जन-जन तक पहुँचाने का जो महान कार्य किया, वह आज भी अद्वितीय माना जाता है। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने धर्म को केवल पुस्तकालयों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे आम जन के जीवन का हिस्सा बना दिया।

उनके द्वारा संपादित 'कल्याण' पत्रिका एक ऐसी आध्यात्मिक धारा थी, जिसमें विभिन्न संप्रदायों के विचार एक साथ प्रवाहित होते थे। वैष्णव, निम्बार्क, रामानन्द, रामानुज और अन्य अनेक परंपराओं के आचार्यों के विचारों को उन्होंने समान आदर के साथ प्रकाशित किया। उनके लिए कोई भी संप्रदाय छोटा या बड़ा नहीं था, बल्कि सभी ईश्वर की ओर जाने वाले मार्ग थे। यही कारण था कि उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया और सभी के प्रति समान श्रद्धा बनाए रखी।

भाई जी के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग उनके अद्भुत आत्मसंयम और दूरदर्शिता को दर्शाता है। अनेक संप्रदायों के आचार्यों ने उन्हें अपने-अपने पंथ में दीक्षित करने का आग्रह किया, किन्तु उन्होंने अत्यंत विनम्रता के साथ इसे अस्वीकार कर दिया। उनका उत्तर अत्यंत गहन था—यदि वे किसी एक संप्रदाय में दीक्षित हो जाते, तो 'कल्याण' पत्रिका की निष्पक्षता पर आंच आ सकती थी। यह उत्तर केवल एक साधारण तर्क नहीं था, बल्कि उसमें एक गहरी आध्यात्मिक समझ और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना निहित थी।

उनका यह निर्णय दर्शाता है कि वे अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक लाभ से अधिक समाज के व्यापक हित को महत्व देते थे। उन्होंने यह समझ लिया था कि यदि वे किसी एक पहचान में बंध जाएंगे, तो वे उस समन्वय की भावना को जीवित नहीं रख पाएंगे, जिसे वे समाज में स्थापित करना चाहते थे। यही कारण है कि उन्होंने स्वयं को किसी एक संप्रदाय की सीमाओं में नहीं बांधा, बल्कि सभी के लिए समान रूप से खुले रहे।

एक बार जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि वे किस संप्रदाय के अनुयायी हैं, तो उनका उत्तर उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का सार बन गया। उन्होंने कहा कि वे 'भगवत संप्रदाय' के एक अकिंचन सेवक हैं। इस उत्तर में उनकी विनम्रता, समर्पण और व्यापक दृष्टिकोण तीनों स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। 'अकिंचन' का अर्थ है—जिसके पास कुछ भी अपना नहीं है, जो पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित है। इस प्रकार उन्होंने स्वयं को किसी भी प्रकार के अहंकार और सीमाओं से मुक्त कर दिया और केवल सेवा को अपना धर्म मान लिया।

भाई जी का यह दृष्टिकोण आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है। वर्तमान समाज में जहाँ संकीर्णता, असहिष्णुता और विभाजन की प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं, वहाँ उनका जीवन एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो हमें सही दिशा दिखाता है। उन्होंने यह सिखाया कि सच्चा धर्म दूसरों को गलत साबित करने में नहीं, बल्कि सभी को साथ लेकर चलने में है। जब हम दूसरों के विचारों और विश्वासों का सम्मान करते हैं, तभी वास्तविक समरसता स्थापित होती है। उनकी विनम्रता भी उनके व्यक्तित्व का एक अत्यंत आकर्षक पहलू थी। इतनी बड़ी संस्था के संस्थापक होने के बावजूद उन्होंने कभी स्वयं को श्रेष्ठ नहीं माना। वे स्वयं को सदैव एक साधारण सेवक के रूप में देखते थे। यही कारण है कि उनके कार्यों में एक विशेष प्रकार की पवित्रता और निष्कपटता दिखाई देती है। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्ची महानता पद या प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि सेवा और विनम्रता में होती है।

'कल्याण' पत्रिका के माध्यम से उन्होंने जो कार्य किया, वह केवल धार्मिक ज्ञान का प्रसार नहीं था, बल्कि वह एक सांस्कृतिक और नैतिक जागरण का अभियान था। उन्होंने विभिन्न संतों और आचार्यों के विचारों को एक मंच पर लाकर यह सिद्ध किया कि विविधता के बावजूद एकता संभव है। यह संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना उस समय था, क्योंकि आज भी समाज को ऐसे ही समन्वय और संतुलन की आवश्यकता है।

भाई जी का जीवन यह भी दर्शाता है कि आध्यात्मिकता केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह समाज के प्रति जिम्मेदारी और सेवा के रूप में भी प्रकट होती है। उन्होंने अपने जीवन को समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया और यह सिद्ध किया कि यदि व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कार्य करे, तो वह समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। अंततः, Hanuman Prasad Poddar का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने संकीर्ण दृष्टिकोण से ऊपर उठकर व्यापक सोच अपनाएं। उनका 'अकिंचन सेवक' होने का भाव हमें यह सिखाता है कि जब तक हम अपने अहंकार और सीमाओं को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम वास्तविक आध्यात्मिकता को प्राप्त नहीं कर सकते। उनका जीवन एक अमूल्य धरोहर है, जो हमें यह संदेश देता है कि सच्चा धर्म वही है, जो सबको जोड़ता है, सबका सम्मान करता है और समस्त मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है।

शोक से परे सवालों की गूंज

समूचा हिंदी जगत एक गहरी उदासी में डूबा हुआ है। किसी एक व्यक्ति का जाना केवल एक परिवार का नुकसान नहीं होता, वह एक युग, एक संवेदना और एक विचारधारा का अवसान भी होता है। विनोद जी के जाने के बाद जो खालीपन बना है, वह केवल शब्दों में नहीं समा सकता। लोग उन्हें अपनी-अपनी तरह से याद कर रहे हैं—किसी के पास उनकी कविताएं हैं, किसी के पास उनके साथ बिताए गए क्षण, किसी के पास उनकी मुस्कान की स्मृति। सोशल मीडिया इन स्मृतियों से भरा पड़ा है, जैसे हर कोई अपनी तरफ से उन्हें थोड़ी देर और जीवित रखने की कोशिश कर रहा हो।

कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के जीवन की वास्तविक ऊँचाई का एहसास उसके जाने के बाद होता है। यह बात आज और भी सच लग रही है। लेकिन इस गहरे दुख के बीच एक और सच्चाई है, जो भीतर कहीं चुभती रहती है—वह सच्चाई जो उनके घर जाकर, उस वातावरण को महसूस करके और उनके अंतिम दिनों की कहानी सुनकर सामने आती है।

जब मैं और माया आंटी उनके घर पहुँचे, तो सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले हुआ करता था। वही मौलश्री का पेड़, जिसकी छाया में कभी बातचीत का सिलसिला चलता था। वही झूला, जो अब स्थिर था, जैसे समय वहीं थम गया हो। वही पंछियों का डेरा, जो रोज़ की तरह आकर बैठते थे, मानो उन्हें अब भी उम्मीद हो कि कोई उन्हें दाना डालेगा। लेकिन जो नहीं था, वह सबसे अधिक महसूस हो रहा था—वह इंतज़ार करती हुई आँखें, वह सहज मुस्कान, वह अपनापन जो हर बार दरवाज़े पर खड़ा मिलता था।

इस बार दरवाज़े पर शाश्वत थे, जैसे हमेशा होते थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर एक अजीब सी थकान और खालीपन था। कमरे में प्रवेश करते ही जो दृश्य सामने आया, उसे स्वीकार करना कठिन था। वहाँ विनोद जी नहीं थे, उनकी एक तस्वीर थी—माला चढ़ी हुई। वह तस्वीर जैसे एक कठोर सत्य की तरह सामने खड़ी थी, जिसे मन स्वीकार करने से इंकार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस अभी वह दरवाज़े से अंदर आएँगे, मुस्कुराएँगे और पूछेंगे—आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई?

लेकिन सच इतना सरल नहीं होता। वह अपनी पूरी कठोरता के साथ सामने आता है और हमें मजबूर करता है कि हम उसे स्वीकार करें। इस स्वीकार के साथ ही मन में एक और सवाल उठता है—क्या यह अंत ऐसा ही होना चाहिए था?

जब एक ओर सोशल मीडिया पर लोग उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहे थे, उनके प्रति अपना स्नेह और सम्मान व्यक्त कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर वह अस्पताल की अव्यवस्था, लापरवाही और उदासीनता से जूझ रहे थे। यह विरोधाभास केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे पूरे स्वास्थ्य तंत्र की सच्चाई को उजागर करता है।

विनोद जी को फेफड़ों में पानी भरने की समस्या के कारण अस्पताल ले जाया गया था। यह एक ऐसी स्थिति थी, जिसका समय पर और सही उपचार किया जाए तो उसे संभाला जा सकता है। लेकिन जो हुआ, वह केवल एक बीमारी का परिणाम नहीं था। वह उन अनेक छोटी-बड़ी लापरवाहियों का परिणाम था, जो धीरे-धीरे मिलकर एक बड़े संकट में बदल जाती हैं।

कहा जाता है कि उन्होंने अपनी बीमारी से हार नहीं मानी, बल्कि अस्पताल में मिली अव्यवस्था और लापरवाही के कारण जीवन से हार गए। यह बात केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रश्न है, जो हमारे पूरे सिस्टम के सामने खड़ा है।

शाश्वत की कोशिशें, उनकी दौड़-भाग, उनकी गुहार—ये सब एक बेटे की अपने पिता को बचाने की अंतिम कोशिशें थीं। वह यहाँ से वहाँ भटकते रहे, लोगों से मिले, प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन उनकी आवाज़ समय पर क्यों नहीं सुनी गई? क्या एक आम नागरिक की आवाज़ इतनी कमजोर हो गई है कि उसे सुने जाने के लिए पहले उसे सोशल मीडिया पर वायरल होना पड़ता है?

जब स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया पर यह मुद्दा उठा, तब कहीं जाकर कुछ हलचल हुई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह 'देर' ही सबसे बड़ा सवाल है। क्या हमारे तंत्र में संवेदनशीलता इतनी कम हो गई है कि किसी की जान जाने के बाद ही हम जागते हैं? शाश्वत की आँखों में जो दर्द था, वह केवल अपने पिता को खोने का नहीं था, बल्कि उस असहायता का भी था, जिसमें उन्होंने सब कुछ होते हुए भी कुछ न कर पाने की पीड़ा महसूस की। उनका यह कहना कि "मैंने तो अपने पिता को खो दिया, लेकिन किसी और के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए"—यह केवल एक भावुक वाक्य नहीं है, बल्कि एक गहरी चेतावनी है।

यह चेतावनी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में एक ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं, जहाँ जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित है? क्या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी सक्षम है कि वह हर व्यक्ति को समय पर और सही उपचार दे सके?

विनोद जी का जाना एक व्यक्तिगत क्षति जरूर है, लेकिन उससे कहीं अधिक यह एक सामूहिक विफलता की कहानी है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने समाज और व्यवस्था को सही दिशा में ले जा रहे हैं? आज जब हम उनके जाने पर शोक व्यक्त कर रहे हैं, उनकी कविताओं को याद कर रहे हैं, उनकी स्मृतियों को संजो रहे हैं, तब हमें उन सवालों को भी नहीं भूलना चाहिए, जो इस घटना ने हमारे सामने खड़े किए हैं। क्योंकि यदि हम इन सवालों से मुँह मोड़ लेंगे, तो यह उदासी केवल एक भावना बनकर रह जाएगी, कोई बदलाव नहीं ला पाएगी।

वह घर आज भी उदास है। मौलश्री का पेड़ जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा है। पंछी आज भी आते हैं, लेकिन जैसे उन्हें भी कुछ कमी महसूस होती है। और हम सब—हम भी इस उदासी का हिस्सा हैं।

लेकिन इस उदासी से बड़े कुछ सवाल हैं, जो लगातार हमारे भीतर गूंज रहे हैं। ये सवाल जवाब मांगते हैं—सिस्टम से, समाज से, हमसे। और जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक यह उदासी केवल एक भाव नहीं रहेगी, बल्कि एक अधूरी कहानी बनकर हमारे भीतर जीवित रहेगी।

अभियान

आस्था, उपचार और आत्मबल का संगम: शिव के 'हीलिंग मंदिर' की अनूठी परंपरा

भारत की आध्यात्मिक परंपरा में मंदिर केवल पूजा-अर्चना के स्थान नहीं रहे, बल्कि वे मनुष्य के मानसिक, भावनात्मक और कभी-कभी शारीरिक संतुलन के केंद्र भी माने जाते रहे हैं। यहां धर्म और जीवन का संबंध इतना गहरा है कि व्यक्ति अपनी समस्याओं, पीड़ा और आशाओं को लेकर ईश्वर के समक्ष उपस्थित होता है और वहीं से उसे संबल, साहस और दिशा मिलती है। दक्षिण भारत के Tamil Nadu में स्थित Thiruneelakudi का Neelakandeswarar Temple इसी आस्था और विश्वास का एक जीवंत उदाहरण है, जिसे लोग श्रद्धा से 'हीलिंग टेंपल' के रूप में जानते हैं।

यह मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि एक विशेष मान्यता के कारण भी अत्यंत लोकप्रिय हो चुका है। यहां आने वाले अनेक भक्त विशेष रूप से थायराइड और महिलाओं में होने वाली पीसीओएस जैसी समस्याओं से राहत की कामना लेकर आते हैं। यद्यपि यह कोई चिकित्सीय उपचार केंद्र नहीं है और न ही इसका कोई वैज्ञानिक दावा किया जाता है, फिर भी लोगों की आस्था और अनुभव इसे एक अलग पहचान प्रदान करते हैं। यह वही स्थान है, जहां व्यक्ति केवल दवा नहीं, बल्कि विश्वास और मनोबल की शक्ति लेकर लौटता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा Neelkanth रूप में की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब उसमें से एक भयंकर विष निकला, जिसने पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया। उस समय भगवान शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस विष की तीव्रता के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे 'नीलकंठ' कहलाए। इस कथा का प्रतीकात्मक अर्थ भी अत्यंत गहरा है—यह त्याग, धैर्य और पीड़ा को सहकर भी दूसरों के कल्याण का संदेश देती है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसी पीड़ा को शांत करने के लिए माता पार्वती ने भगवान शिव के कंठ पर तेल अर्पित किया था। इसी परंपरा की स्मृति में इस मंदिर में भी विशेष रूप से तेल चढ़ाने की प्रथा है। भक्तजन मानते हैं कि जिस प्रकार भगवान शिव के कंठ की जलन शांत हुई, उसी प्रकार उनके अपने गले और हार्मोन से जुड़ी समस्याएं भी शांत हो सकती हैं। यह विश्वास ही उन्हें यहां तक खींच लाता है और उनके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इस मंदिर की एक विशेष पहचान इसकी 'विभूति' है, जिसे अत्यंत पवित्र और चमत्कारिक माना जाता है। भक्तजन इस विभूति को अपने गले पर लगाते हैं और इसे अपनी समस्याओं के समाधान का माध्यम मानते हैं। यह विभूति केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह विश्वास, आशा और आत्मबल का प्रतीक बन जाती है। जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ इसे ग्रहण करता है, तो उसके भीतर एक नई शक्ति का संचार होता है, जो उसे अपनी बीमारी से लड़ने के लिए प्रेरित करती है।

यहां आने वाली महिलाओं में विशेष रूप से पीसीओएस जैसी समस्या से जूझ रही महिलाएं होती हैं। आधुनिक जीवनशैली, तनाव, खान-पान की अनियमितता और हार्मोनल असंतुलन के कारण यह समस्या आज के समय में तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में जब चिकित्सा उपचार के साथ-साथ मानसिक तनाव भी बढ़ता है, तब व्यक्ति को किसी ऐसे सहारे की आवश्यकता होती है, जो उसे भावनात्मक संतुलन प्रदान कर सके। यह मंदिर उसी भावनात्मक सहारे का केंद्र बन जाता है, जहां महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर आती हैं और मानसिक रूप से सशक्त होकर लौटती हैं।

थायराइड जैसी समस्याएं भी आज के समय में आम हो चुकी हैं, जो सीधे तौर पर गले और हार्मोनल संतुलन से जुड़ी होती हैं। इस मंदिर में आकर लोग अपने गले पर विभूति लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं कि उन्हें राहत मिलेगी। यह विश्वास भले ही वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध न हो, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह व्यक्ति को सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास प्रदान करता है, जो किसी भी उपचार प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।

यह समझना भी आवश्यक है कि ऐसे मंदिरों की भूमिका चिकित्सा उपचार का विकल्प नहीं होती, बल्कि यह एक पूरक के रूप में कार्य करते हैं। जब व्यक्ति अपने मन को शांत करता है, तनाव से मुक्त होता है और सकारात्मक ऊर्जा से भरता है, तो उसका शरीर भी उपचार की दिशा में बेहतर प्रतिक्रिया देता है। इस दृष्टि से देखा जाए, तो यह मंदिर एक प्रकार से मानसिक और आध्यात्मिक उपचार का केंद्र बन जाता है। तमिलनाडु में ही स्थित Vaitheeswaran Koil भी इसी परंपरा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां भगवान शिव को 'वैद्य' के रूप में पूजा जाता है। यहां का सिद्धामृतम कुंड विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसके जल को औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है। भक्तजन इस जल का सेवन करते हैं और इसे त्वचा संबंधी रोगों से राहत दिलाने वाला मानते हैं। इस प्रकार, दक्षिण भारत में कई ऐसे मंदिर हैं, जहां आध्यात्मिकता और उपचार की अवधारणाएं एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। इन सभी मान्यताओं के पीछे सबसे महत्वपूर्ण तत्व है—आस्था। आस्था वह शक्ति है, जो मनुष्य को निराशा से आशा की ओर ले जाती है। जब व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति में होता है, तो उसे केवल दवाओं की नहीं, बल्कि मानसिक सहारे की भी आवश्यकता होती है। मंदिर, पूजा और प्रार्थना इसी मानसिक सहारे का माध्यम बनते हैं। यह व्यक्ति को यह विश्वास दिलाते हैं कि वह अकेला नहीं है और एक उच्च शक्ति उसके साथ है।

आज के आधुनिक युग में, जहां विज्ञान और तकनीक ने चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है, वहीं यह भी सत्य है कि केवल शारीरिक उपचार ही पर्याप्त नहीं होता। मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन भी उतने ही आवश्यक हैं। ऐसे में ये मंदिर एक संतुलन प्रदान करते हैं, जहां व्यक्ति आधुनिक चिकित्सा के साथ-साथ आध्यात्मिक शक्ति का भी सहारा ले सकता है।

अंततः, Neelakandeswarar Temple केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, आत्मबल और आशा का प्रतीक है। यहां आने वाले लोग केवल अपनी समस्याओं का समाधान ही नहीं खोजते, बल्कि वे अपने भीतर एक नई ऊर्जा और विश्वास लेकर लौटते हैं। यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और विश्वास से भी किया जा सकता है। जब आस्था और प्रयास एक साथ चलते हैं, तब ही सच्चा संतुलन और उपचार संभव होता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

महिला आरक्षण पर सियासी संग्राम: 'दशकों तक दबाए रखा मुद्दा', कांग्रेस पर भाजपा का तीखा प्रहार

(जीएनएस)। शिमला से उठी एक राजनीतिक आवाज ने पूरे देश में महिला आरक्षण के मुद्दे को फिर से केंद्र में ला खड़ा किया है। हिमाचल प्रदेश से भाजपा सांसद Sikandar Kumar द्वारा कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों ने न केवल सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है, बल्कि उस लंबे इतिहास को भी फिर से सामने ला दिया है, जिसमें महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का सवाल बार-बार उठा, लेकिन हर बार अधूरा रह गया। यह विवाद केवल वर्तमान राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दशकों का राजनीतिक इतिहास, नीतिगत असहमति, सामाजिक जटिलताएं और सत्ता की प्राथमिकताएं शामिल हैं।

सांसद सिकंदर कुमार ने अपने बयान में कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने अपने लंबे शासनकाल के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को प्राथमिकता नहीं दी। उनका कहना है कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव कई बार चर्चा में आया, लेकिन उसे लागू करने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखाई गई। यह आरोप उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को छूता है, जब 1990 के दशक से लेकर 2000 के दशक तक महिला आरक्षण विधेयक बार-बार संसद में पेश हुआ, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से पारित नहीं हो सका। कभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई, तो कभी सामाजिक समीकरणों और जातीय प्रतिनिधित्व के सवालों ने इसे उलझा दिया।

भारतीय राजनीति में महिला आरक्षण का मुद्दा हमेशा से जटिल रहा है। एक ओर इसे महिलाओं के सशक्तिकरण और समान भागीदारी का माध्यम माना गया, तो दूसरी ओर इसके भीतर आरक्षण के भीतर आरक्षण, क्षेत्रीय संतुलन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे कई सवाल उठे। यही कारण रहा कि यह विधेयक दशकों तक राजनीतिक बहस का हिस्सा बना रहा, लेकिन ठोस रूप नहीं ले सका। इस पृष्ठभूमि में जब वर्तमान सरकार ने Nari Shakti Vandan Act को पारित किया, तो इसे एक ऐतिहासिक कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसने लंबे समय से लंबित इस मुद्दे को कानूनी आधार प्रदान किया।

सिकंदर कुमार का दावा है कि यह कानून केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में एक बड़ा बदलाव है, जो महिलाओं की भागीदारी को संस्थागत रूप से मजबूत करेगा। उनका कहना है कि इससे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी और नीति-निर्माण में उनकी भूमिका अधिक प्रभावी होगी। उनके अनुसार, यह कदम देश की लगभग आधी आबादी को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

हालांकि, इस मुद्दे का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि महिला आरक्षण का विचार नया नहीं है और इसे पहले भी कई बार आगे बढ़ाया गया था। उनका तर्क है कि वर्तमान सरकार ने जिस कानून को पारित किया है, उसकी जड़ें पिछले प्रयासों में ही निहित हैं। इसके अलावा, विपक्ष यह भी सवाल उठाता रहा है कि इस कानून को लागू करने में देरी क्यों हो रही है और इसे जनगणना व परिसीमन से जोड़ने की क्या आवश्यकता है। यह बहस इस मुद्दे को और जटिल बना देती है, क्योंकि कानून बनना एक बात है, लेकिन उसका वास्तविक क्रियान्वयन दूसरी।

राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो महिला आरक्षण अब केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह चुनावी रणनीति और जनसंपर्क का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। भाजपा इसे अपनी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रही है और महिलाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रही है, जबकि कांग्रेस इस पर अपनी ऐतिहासिक भूमिका को सामने रखकर राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। इस प्रक्रिया में दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं, जिससे यह मुद्दा और अधिक चर्चा में बना हुआ है।

सामाजिक दृष्टिकोण से यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत जैसे देश में, जहां महिलाओं की आबादी लगभग आधी है, वहां उनकी राजनीतिक भागीदारी लंबे समय तक सीमित रही है। पंचायत स्तर पर आरक्षण लागू होने के बाद महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उनकी संख्या अभी भी अपेक्षाकृत कम है। ऐसे में महिला आरक्षण को एक ऐसे कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो इस असंतुलन को दूर कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। क्या केवल आरक्षण देने से महिलाओं की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी? क्या वे स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पाएंगी या फिर राजनीतिक परिवारों और दलों के प्रभाव में रहेंगी? क्या यह कदम जमीनी स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा या केवल प्रतिनिधित्व तक सीमित रह जाएगा? ये ऐसे सवाल हैं, जिनका उत्तर समय के साथ ही मिल पाएगा।

इस पूरे विवाद के बीच यह भी ध्यान देने योग्य है कि महिला आरक्षण केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का भी प्रतीक है। जब महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होंगी, तो नीतियों में भी उनके दृष्टिकोण का प्रभाव दिखाई देगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे मुद्दों पर अधिक संवेदनशील और समावेशी नीतियां बनने की संभावना बढ़ेगी।

सिकंदर कुमार द्वारा लगाए गए आरोप और कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस बात को दर्शाती है कि महिला आरक्षण का मुद्दा अभी भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। यह केवल कानून बनने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके क्रियान्वयन, प्रभाव और राजनीतिक उपयोग को लेकर भी बहस जारी है। शिमला से उठी यह आवाज देशभर में गूंज रही है और यह संकेत दे रही है कि आने वाले समय में यह मुद्दा और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

अंततः, यह कहा जा सकता है कि महिला आरक्षण पर चल रही यह सियासी जंग केवल वर्तमान राजनीति का हिस्सा नहीं, बल्कि एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का परिणाम है। यह संघर्ष केवल महिलाओं के अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे लोकतंत्र के लिए है, जहां हर वर्ग की समान भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अब यह देखना बाकी है कि यह बहस किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या वास्तव में वह बदलाव ला पाती है, जिसकी उम्मीद देश की करोड़ों महिलाएं वर्षों से कर रही हैं।

बीमार व्यवस्था का दर्द: 22 लाख आबादी पर सिर्फ 45 डॉक्टर, किशनगंज में स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ती हुईं

(जीएनएस)। किशनगंज की जमीन पर खड़ी हकीकत किसी आंकड़े की ठंडी भाषा नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की पीड़ा की कहानी है जिनके लिए इलाज अब एक अधिकार नहीं, बल्कि एक कठिन जंग बन चुका है। करीब 22 लाख की आबादी वाले इस जिले में महज 45 डॉक्टरों का होना अपने आप में उस असंतुलन को उजागर करता है, जो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में गहराई तक पैठ बना चुका है। इस गंभीर स्थिति को लेकर कांग्रेस सांसद Dr. Mohammad Javed Azad ने जो सवाल उठाए हैं, वे केवल राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक ऐसे संकट की ओर इशारा करते हैं जिसे लंबे समय से नजरअंदाज किया जाता रहा है। यह स्थिति केवल डॉक्टरों की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे स्वास्थ्य ढांचे की कमजोरी का परिणाम है। जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पताल तक मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन संसाधनों और स्टाफ की कमी के कारण व्यवस्था चरमराई हुई है। एक डॉक्टर पर औसतन 48 हजार से अधिक लोगों की जिम्मेदारी होना इस बात का संकेत है कि मरीजों को समय पर इलाज मिलना लगभग असंभव हो गया है। गंभीर बीमारियों के मामलों में तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जहां देरी सीधे जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन जाती है।

ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह संकट और गहरा है। वहां न तो पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं हैं और न ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता। कई गांवों के लोग आज भी मामूली इलाज के लिए लंबी दूरी तय करने को मजबूर हैं। बारिश, खराब सड़कें और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं इस संघर्ष को और कठिन बना देती हैं। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह स्थिति किसी खतरे से कम नहीं है, जहां हर छोटी बीमारी भी बड़ी समस्या का रूप ले सकती है।

सांसद ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आवश्यक नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं और उपलब्ध संसाधनों का भी प्रभावी उपयोग नहीं हो पा रहा है। उनका कहना है कि यदि समय रहते डॉक्टरों की भर्ती और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में यह संकट और गहरा सकता है। यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि आम जनता के अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसे प्राथमिकता के साथ हल किया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य के इस गंभीर संकट के साथ-साथ उन्होंने महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को भी जोड़ा। उन्होंने Nari Shakti Vandan Act के लागू होने में हो रही देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि यह कानून समय पर लागू होता, तो देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती और नीतिगत निर्णयों में उनकी भूमिका अधिक प्रभावी होती। उनका मानना है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में ज्यादा संवेदनशील और प्रभावी नीतियां बन सकती हैं। इसके अलावा, उन्होंने बिहार में रोजगार के संकट पर भी चिंता जताई। उनके अनुसार, राज्य की लगभग 13 करोड़ की आबादी में से करीब 3 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर चुके हैं। यह पलायन केवल आर्थिक मजबूरी नहीं, बल्कि राज्य की विकास नीतियों की सीमाओं को भी दर्शाता है। जब स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर नहीं मिलते, तो लोग अपने परिवार और सामाजिक जड़ों को छोड़कर बाहर जाने को मजबूर हो जाते हैं।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र की दमदार छलांग: मुनाफा 35% उछला, आय और एसेट क्वालिटी में भी बड़ा सुधार

(जीएनएस)। नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने वित्तीय परिणामों से बाजार को सकारात्मक संकेत दिए हैं। जनवरी से मार्च के बीच की इस अवधि में बैंक का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 35 प्रतिशत की मजबूत बढ़त के साथ 2,014 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,493 करोड़ रुपये था। यह वृद्धि केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि बैंक की रणनीतिक मजबूती, बेहतर प्रबंधन और जोखिम नियंत्रण की दिशा में उठाए गए कदमों का भी स्पष्ट संकेत देती है। बैंक की कुल आय में भी उल्लेखनीय उछाल दर्ज किया गया है। चौथी तिमाही में यह बढ़कर 8,693 करोड़ रुपये हो गई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 7,711 करोड़ रुपये थी। यानी लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि यह दर्शाती है कि बैंक का कारोबार लगातार विस्तार कर रहा है और

उसकी आय के स्रोत मजबूत हो रहे हैं। इस वृद्धि के पीछे सबसे बड़ा योगदान ब्याज आय का रहा, जो सालाना आधार पर करीब 15 प्रतिशत बढ़कर 7,755 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यह साफ संकेत है कि बैंक का लोन पोर्टफोलियो बढ़ा है और ऋण वितरण के जरिए उसकी कमाई में स्थिरता आई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ब्याज आय में यह वृद्धि केवल कर्ज देने की मात्रा बढ़ने से नहीं, बल्कि बेहतर एसेट मिक्स और ब्याज दरों के कुशल प्रबंधन का भी परिणाम है। बैंक ने जिस तरह से अपने लोन बुक को विविधता दी है और जोखिम वाले क्षेत्रों में एक्सपोजर को नियंत्रित किया है, उसने उसकी कमाई को स्थायित्व प्रदान किया है।

एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर भी बैंक ने उल्लेखनीय सुधार दिखाया है, जो किसी भी वित्तीय संस्थान की दीर्घकालिक मजबूती का सबसे बड़ा संकेतक होता है। सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (GNPA) घटकर मार्च 2026 के अंत तक 1.45 प्रतिशत रह गईं, जो पिछले साल इसी समय 1.74 प्रतिशत थीं। इसी तरह, शुद्ध एनपीए (NNPA) भी घटकर 0.13 प्रतिशत पर आ गया, जो एक साल पहले 0.18 प्रतिशत था। यह गिरावट इस बात का प्रमाण है कि बैंक ने अपने खराब कर्जों की वसूली और जोखिम प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार किया है।

एनपीए में यह कमी न केवल बैंक की बैलेंस शीट को मजबूत करती है, बल्कि निवेशकों के विश्वास को भी बढ़ाती है। जब किसी बैंक की एसेट क्वालिटी सुधरती है, तो उसका सीधा असर उसकी लाभप्रदता और भविष्य की विकास संभावनाओं पर पड़ता है। यही कारण है कि बाजार विशेषज्ञ इस प्रदर्शन को बैंक के लिए एक सकारात्मक मोड़ मान रहे हैं।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र का यह प्रदर्शन ऐसे समय में आया है, जब बैंकिंग सेक्टर प्रतिस्पर्धा, ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। इसके बावजूद बैंक ने जिस तरह से अपने वित्तीय संकेतकों में सुधार किया है, वह उसके मजबूत संचालन और रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, मुनाफे में यह तेज वृद्धि, आय में विस्तार और एनपीए में गिरावट का संतुलित संयोजन बैंक को आने वाले समय में और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। इससे न केवल ऋण वितरण की गति बढ़ेगी, बल्कि नए क्षेत्रों में निवेश और विस्तार की संभावनाएं भी खुलेंगी। साथ ही, यह प्रदर्शन अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।

कुल मिलाकर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने चौथी तिमाही में जो परिणाम पेश किए हैं, वे यह संकेत देते हैं कि बैंक न केवल वर्तमान में मजबूत स्थिति में है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। निवेशकों और बाजार के लिए यह एक भरोसेमंद संकेत है कि बैंकिंग सेक्टर में स्थिरता और विकास की संभावनाएं अभी भी मजबूत बनी हुई हैं।

'ऑपरेशन ऑक्टोपस 2.0' का बड़ा खुलासा: 9 राज्यों में फैले साइबर फ्रॉड रैकेट पर शिकंजा, 52 गिरफ्तार

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देशभर में तेजी से फैल रहे साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हैदराबाद पुलिस ने 'ऑपरेशन ऑक्टोपस 2.0' के तहत एक संगठित साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस व्यापक ऑपरेशन में 9 राज्यों में समन्वित छापेमारी कर कुल 52 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें चौंकाने वाली बात यह है कि 32 आरोपी विभिन्न बैंकों के कर्मचारी हैं। इस खुलासे ने बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और आंतरिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पुलिस के अनुसार, यह पूरा नेटवर्क साइबर अपराधियों और बैंक कर्मचारियों के गठजोड़ से संचालित हो रहा था, जिसमें 'म्यूल अकाउंट' यानी फर्जी बैंक खातों के जरिए अवैध धन के लेन-देन को अंजाम दिया जा रहा था। इन खातों का उपयोग ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, और अन्य डिजिटल फ्रॉड से प्राप्त रकम को इधर-उधर करने और उसे वैध दिखाने के लिए किया जाता था। जांच में सामने आया है कि कुछ बैंक कर्मचारी

जानबूझकर केवाईसी प्रक्रिया में ढील देते थे या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खाते खोलने में मदद करते थे।

गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों में बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक और इंडसइंड बैंक जैसे प्रमुख बैंकों के मैनेजर, क्लर्क और केवाईसी स्टाफ शामिल हैं। यह तथ्य इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना देता है, क्योंकि जिन संस्थानों पर आम जनता अपने पैसों की सुरक्षा का भरोसा करती है, वहीं के कुछ कर्मचारी इस तरह के अपराधों में संलिप्त पाए गए। यह ऑपरेशन एक सप्ताह तक चला, जिसमें पुलिस की कई टीमें अलग-अलग राज्यों में सक्रिय रहीं। महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना समेत अन्य राज्यों में एक साथ छापेमारी कर इस नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। छापों के दौरान पुलिस ने 26 मोबाइल फोन, 14 चेक बुक, 21 फर्जी कंपनियों की मुहरें और कई अन्य संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए हैं। अधिकारियों के अनुसार, इन सामग्रियों का इस्तेमाल फर्जी कंपनियों के नाम पर खाते खोलने और उन्हें संचालित करने में किया जाता था, जिससे अवैध धन को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह नेटवर्क काफी समय से सक्रिय था और देश के अलग-अलग हिस्सों में फैले साइबर अपराधियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा था। इस ऑपरेशन के जरिए न केवल अपराधियों की एक बड़ी कड़ी को तोड़ा गया है, बल्कि यह भी संकेत मिला है कि साइबर फ्रॉड अब एक संगठित उद्योग का रूप ले चुका है, जिसमें तकनीक के साथ-साथ सिस्टम के अंदर बैठे लोग भी शामिल हो रहे हैं। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड और इसके अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की भी जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि इस मामले के तार कई अन्य राज्यों और संभवतः विदेशों तक जुड़े हो सकते हैं। इस कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि साइबर अपराध से निपटने के लिए केवल तकनीकी उपाय पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि संस्थागत पारदर्शिता और जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। 'ऑपरेशन ऑक्टोपस 2.0' न केवल एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि यह एक चेतावनी भी है कि डिजिटल युग में अपराध के तरीके बदल चुके हैं और उनसे निपटने के लिए सतर्कता, सख्ती और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।

डगमगाया बाजार, निवेशकों की जेब पर चोट: उतार चढ़ाव के बीच मामूली बढ़त, 19 हजार करोड़ डूबे

(जीएनएस)। नई दिल्ली। वैश्विक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनाव के बीच घरेलू शेयर बाजार ने सोमवार को ऐसा उतार-चढ़ाव भरा दिन देखा, जिसने निवेशकों की धड़कनें बढ़ा दीं। दिनभर के भारी उतार-चढ़ाव के बाद भले ही BSE Sensex और Nifty 50 हल्की बढ़त के साथ बंद हुए, लेकिन बाजार की अंदरूनी कमजोरी ने निवेशकों को तगड़ा झटका दिया। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में तेज बिकवाली के कारण एक ही दिन में करीब 19 हजार करोड़ रुपये की पूंजी साफ हो गई, जो इस बात का संकेत है कि बाजार की मजबूती सतही थी, जबकि अंदर से दबाव गहराता जा रहा है। कारोबार की शुरुआत उत्साहजनक रही थी। सेंसेक्स बढ़त के साथ खुलकर शुरुआती सत्र में ऊंचे स्तर तक पहुंचा, जिससे निवेशकों में सकारात्मक माहौल बना। इसी तरह निफ्टी ने भी मजबूत शुरुआत की और शुरुआती घंटों में अच्छी बढ़त दर्ज की। लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ा, बाजार में बिकवाली का दबाव हावी होता गया। खासकर दोपहर के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी, जिससे सूचकांक अपने उच्च स्तर से नीचे खिसक गए। हालांकि, अंत में हल्की रिकवरी के चलते दोनों इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहे।

सेक्टोरल स्तर पर तस्वीर मिश्रित रही। ऑटोमोबाइल और पीएसयू बैंकिंग शेयरों में खरीदारी का रुख देखने को मिला, जिससे इन सेक्टरों ने बाजार को कुछ सहारा दिया। इसके अलावा कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी मजबूती बनी रही। वहीं दूसरी ओर आईटी, रियल्टी और टेलीकॉम सेक्टर में दबाव साफ नजर आया। एफएमसीजी, हेल्थकेयर और मेटल शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई, जिसने बाजार की व्यापक कमजोरी को उजागर किया।

ब्रॉडर मार्केट की हालत और भी चिंताजनक रही। मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि छोटे और मध्यम निवेशकों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल मार्केट कैप घटकर लगभग 465.45 लाख करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले सत्र के मुकाबले करीब 19 हजार करोड़ रुपये कम है। यह गिरावट भले ही प्रतिशत के हिसाब से छोटी लगे, लेकिन निवेशकों के विश्वास पर इसका प्रभाव बड़ा है। मार्केट ब्रेड्थ भी नकारात्मक रही, जो बाजार की असली स्थिति को दर्शाती है। बीएसई में कारोबार करने वाले कुल शेयरों में गिरावट वाले शेयरों की संख्या बढ़त वाले शेयरों से कहीं अधिक रही। एनएसई में भी यही स्थिति देखने को मिली, जहां गिरावट वाले शेयरों ने बढ़त वाले शेयरों को पीछे छोड़ दिया। इसका मतलब साफ है कि बाजार की सीमित बढ़त कुछ बड़े शेयरों के सहारे थी, जबकि अधिकांश शेयर दबाव में रहे। ब्लूचिप कंपनियों की बात करें तो State Bank of India, JSW Steel और Asian Paints जैसे शेयरों में मजबूती देखने को मिली, जिन्होंने बाजार को संभालने में भूमिका निभाई। वहीं Kotak Mahindra Bank और Hindalco Industries जैसे शेयरों में गिरावट ने बाजार पर दबाव बढ़ाया। इसके अलावा Jio Financial Services भी प्रमुख लूजर्स में शामिल रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और संभावित वार्ता को लेकर बनी अनिश्चितता का असर वैश्विक बाजारों पर पड़ा है, जिसका सीधा प्रभाव भारतीय बाजार पर भी देखने को मिला। विदेशी निवेशकों का सतर्क रुख और वैश्विक संकेतों की कमजोरी ने बाजार को सीमित दायरे में बांधे रखा। निवेशक फिलहाल जोखिम लेने से बच रहे हैं और सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर झुकाव दिखा रहे हैं। आने वाले दिनों में बाजार की दिशा काफी हद तक वैश्विक घटनाक्रम, कच्चे तेल की कीमतों, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों और विदेशी निवेशकों की गतिविधियों पर निर्भर करेगी।

स्वस्थ भारत की ओर सूरत का कदम: चैंबर के हेल्थ सेशन में न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव केयर पर विशेषज्ञों का जोर

(जीएनएस)। सूरत। तेजी से भागती जिंदगी, अनियमित खान-पान और बढ़ते तनाव के बीच स्वास्थ्य अब सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। इसी गंभीर मुद्दे को केंद्र में रखते हुए सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रविवार, 19 अप्रैल 2026 को नानपुरा स्थित समृद्धि भवन में एक महत्वपूर्ण हेल्थ अवेयरनेस सेशन का आयोजन किया, जिसमें 'न्यूट्रिशन से डाइजेस्टिव हेल्थ तक – एक हेल्दी और प्रोडक्टिव इंडिया बनाना' विषय पर गहन चर्चा हुई। इस कार्यक्रम ने न केवल उपस्थित लोगों को जागरूक किया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य ही राष्ट्र की उत्पादकता और प्रगति का आधार है।

कार्यक्रम की शुरुआत चैंबर के अध्यक्ष निखिल मद्रासी के स्वागत संबोधन से हुई, जिसमें उन्होंने आज की जीवनशैली पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि लोग काम और सफलता की दौड़ में अपने स्वास्थ्य को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि मानव संसाधन स्वस्थ नहीं होगा, तो किसी भी देश की प्रगति अधूरी रह जाएगी। उन्होंने ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों को समाज के लिए अत्यंत आवश्यक बताते हुए कहा कि यह केवल जानकारी देने का मंच नहीं, बल्कि व्यवहार में बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

इस सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में क्लिनिकल डाइटीशियन और मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट रोशनी पीठावाला ने 'हेल्दी लोग, हेल्दी इंडिया' विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि संतुलित आहार केवल पेट भरने का माध्यम नहीं, बल्कि शरीर की ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक संतुलन का आधार है। उन्होंने

फास्ट फूड और प्रोसेस्ड खाने से दूरी बनाकर ताजे, घर के बने और पोषणयुक्त भोजन को अपनाने पर जोर दिया। उनके अनुसार, सही खान-पान से न केवल बीमारियों से बचा जा सकता है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर बनाई जा सकती है।

डाइजेस्टिव हेल्थ के बढ़ते संकट पर चिंता व्यक्त करते हुए सीनियर एनोरेक्टल सर्जन डॉ. भाविन भुवा ने कहा कि पाइल्स, फिशर और फिस्टुला जैसी समस्याएं अब आम होती जा रही हैं। उन्होंने इसके पीछे खराब खान-पान, फाइबर की कमी, पानी कम पीना और लंबे समय तक बैठे रहने जैसी आदतों को प्रमुख कारण बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि इन बीमारियों को नजरअंदाज करना आगे चलकर गंभीर जटिलताओं को जन्म दे सकता है, इसलिए समय रहते जांच और उपचार बेहद जरूरी है।

इसी क्रम में डॉ. नरेश चौवाटिया ने इन बीमारियों के इलाज और रोकथाम पर व्यावहारिक सुझाव साझा किए। उन्होंने बताया कि नियमित व्यायाम, पर्याप्त पानी का सेवन, स्वच्छता का ध्यान और संतुलित आहार अपनाने से अधिकांश डाइजेस्टिव समस्याओं से बचा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि घरेलू उपाय शुरुआती स्तर पर मददगार हो सकते हैं, लेकिन किसी भी गंभीर समस्या में डॉक्टर की सलाह लेना अनिवार्य है। उनका जोर इस बात पर था कि लोग शर्म या झिझक के कारण इन समस्याओं को छिपाने के बजाय खुलकर चिकित्सा सहायता लें।

कार्यक्रम के दौरान चैंबर ग्रुप के चेयरमैन राकेश गांधी ने सत्र की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस तरह के आयोजन भविष्य में भी जारी रहेंगे, ताकि उद्योग जगत से जुड़े लोगों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा सके। वहीं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हेल्थ कमेटी के को-चेयरमैन निखिल वघासिया ने सत्र का सफल संचालन किया और अंत में सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।

इस पूरे आयोजन ने यह स्पष्ट कर दिया कि स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास का परिणाम है। जब उद्योग, समाज और विशेषज्ञ एक साथ मिलकर जागरूकता फैलाते हैं, तो उसका प्रभाव व्यापक और दीर्घकालिक होता है। सूरत में आयोजित यह सेशन इसी दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित हुआ, जिसने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि अगर जीवन में संतुलन और सफलता चाहिए, तो सबसे पहले स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी।

जनसेवा सर्वोपरि: 25 करोड़ जनता की जिम्मेदारी का संकल्प, 'जनता दर्शन' में सीएम योगी का सख्त संदेश

(जीएनएस)। लखनऊ के सत्ता गलियारों में आयोजित 'जनता दर्शन' कार्यक्रम उस जीवंत लोकतांत्रिक परंपरा की झलक बनकर सामने आया, जहां सत्ता और जनता के बीच की दूरी कम होती दिखाई दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने इस अवसर पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश की करीब 25 करोड़ आबादी की सेवा करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इस दायित्व के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह केवल एक प्रशासनिक निर्देश नहीं था, बल्कि शासन की कार्यशैली और प्राथमिकताओं का सार्वजनिक संकेत भी था, जिसमें जवाबदेही, पारदर्शिता और समयबद्ध समाधान को केंद्र में रखा गया।

'जनता दर्शन' कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोग अपनी समस्याओं और उम्मीदों के साथ मुख्यमंत्री के सामने उपस्थित हुए। यह दृश्य अपने आप में बताता है कि आम नागरिक अब भी सीधे संवाद की इस प्रक्रिया को एक प्रभावी माध्यम मानता है। आवास, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दे बड़ी संख्या में सामने आए, जो यह दर्शाते हैं कि विकास की प्रक्रिया के बावजूद जमीनी स्तर पर कई चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने हर शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि सरकार केवल सुनने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि समाधान की दिशा में तत्काल कदम उठाने का प्रयास कर रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को यह भी चेताया कि शिकायतों के निस्तारण में देरी या लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह संदेश प्रशासनिक तंत्र के लिए एक स्पष्ट संकेत था कि अब केवल कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर परिणाम दिखाने होंगे। शासन की इस सख्ती का उद्देश्य व्यवस्था में सुधार लाना और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करना है।

आर्थिक सहायता से जुड़े मामलों में भी मुख्यमंत्री का रुख सक्रिय और त्वरित दिखाई दिया। बरेली से आई एक महिला की समस्या सुनते ही उन्होंने तत्काल जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि उसे Pradhan Mantri Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) के तहत लाभ दिलाया जाए। यह योजना छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी लगाने वालों के लिए आर्थिक सहारा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है, और ऐसे मामलों में त्वरित हस्तक्षेप यह दर्शाता है कि सरकार योजनाओं को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि जरूरतमंदों तक उसका वास्तविक लाभ पहुंचाना चाहती है।

आवास से जुड़े मामलों में भी बड़ी संख्या में आवेदन सामने आए, जो इस बात का संकेत है कि आज भी एक बड़ी आबादी अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए सरकारी योजनाओं पर निर्भर है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें Pradhan Mantri Awas Yojana और राज्य की आवास योजनाओं के तहत जल्द से जल्द लाभ दिया जाए। यह निर्देश केवल आवास उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। चिकित्सा सहायता के मामलों में मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण संवेदनशील और व्यावहारिक दोनों नजर आया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन मरीजों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, उनके इलाज में आने वाले खर्च का तत्काल आकलन किया जाए और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि समय रहते सहायता उपलब्ध कराई जा सके। यह कदम उन परिवारों के लिए राहत का कारण बन सकता है, जो गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आर्थिक अभाव किसी भी बच्चे की पढ़ाई में बाधा नहीं बनना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में स्कूल प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर समाधान निकाला जाए। यह दृष्टिकोण इस बात को दर्शाता है कि सरकार शिक्षा को केवल एक सेवा नहीं, बल्कि भविष्य निर्माण का आधार मानती है। कार्यक्रम के दौरान कानून-व्यवस्था और अवैध अतिक्रमण से जुड़े मुद्दे भी सामने आए, जिन पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता या अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यह संदेश कानून के शासन को मजबूत करने और नागरिकों में सुरक्षा की भावना पैदा करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कुल मिलाकर, 'जनता दर्शन' कार्यक्रम केवल शिकायत सुनने का मंच नहीं, बल्कि शासन और प्रशासन के बीच एक सक्रिय संवाद का माध्यम बनकर उभरा है। इसमें मुख्यमंत्री की सक्रियता और अधिकारियों की जवाबदेही का जो स्वरूप सामने आया है, वह यह संकेत देता है कि सरकार अब सेवा वितरण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाना चाहती है। 25 करोड़ लोगों की सेवा का संकल्प केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक चुनौती है, जिसे पूरा करने के लिए प्रशासनिक इच्छाशक्ति, संसाधनों का सही उपयोग और निरंतर निगरानी आवश्यक है।

इस पहल का वास्तविक प्रभाव तभी दिखाई देगा, जब इन निर्देशों का पालन जमीनी स्तर पर सुनिश्चित किया जाएगा और आम नागरिक को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होगा। फिलहाल, 'जनता दर्शन' के माध्यम से दिया गया यह संदेश स्पष्ट है कि सरकार जनसेवा को प्राथमिकता देते हुए हर शिकायत को गंभीरता से लेने और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके द्वारा वडोदरा स्टेशन पर क्राउड मैनेजमेंट व्यवस्था की समीक्षा

समर सीज़न के दौरान यात्रिओं की सुविधा के लिए वडोदरा मंडल प्रतिबद्ध

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके द्वारा आज वडोदरा स्टेशन का दौरा किया गया और समर सीज़न के दौरान यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं तथा क्राउड मैनेजमेंट व्यवस्था की समीक्षा की गई।

पश्चिम रेलवे के जनसम्पर्क अधिकारी श्रीअनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने इस दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए सभी अधिकारिओं एवं स्टेशन स्टाफ को यात्रिओं की सुविधा के लिए स्टेशन पर सभी व्यवस्थाओ को सुचारु रखने के निर्देश दिए। यात्रिओं की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए वडोदरा मंडल द्वारा क्राउड मैनेजमेंट के विशेष प्रयास किये गए है। इसके लिए वडोदरा स्टेशन पर 350 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल का एक होल्डिंग एरिया बनाया गया है,जहां यात्री ट्रेन आने से पहले आराम कर सकते हैं होल्डिंग एरिया में सीटिंग व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, पर्याप्त लाइटिंग जैसी मूलभूत सुविधाएं दी गई है। यात्रिओं की सहायता के लिए राउंड द क्लॉक टिकट चेकिंग और रेल सुरक्षा बल के अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की गयी है, जिससे यात्रियों को कोई असुविधा न हो।

यात्री को टिकट लेने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए वडोदरा स्टेशन पर एक्स्ट्रा बुकिंग काउंटर खोले गए हैं। यात्रिओं के लिए टिकटिंग को आसान करते हुए टिकट चेकर द्वारा मोबाइल टिकटिंग की भी व्यवस्था की गयी है। स्टेशन पर यात्रियों की संख्या की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे द्वारा यात्रा की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवान प्रभावी समन्वय बनाए रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ड्यूटी के दौरान निर्बाध डिजिटल संचार के लिए वॉकी-टॉकी का उपयोग कर रहें हैं।

पश्चिम रेलवे का वड़ोदरा मंडल की आप सभी से अपील है टिकट खरीद कर यात्रा करें और स्टेशन पर उपलब्ध रेलवे कर्मचारियों के दिशा निर्देशों का पालन करें। पश्चिम रेलवे यात्रिओं के सफर को सुविधाजनक और आरामदायक बनाए के लिए प्रतिबध्द है।

उधना स्टेशन भगदड़ पर सियासत और सवाल: रेलवे के 'यू-टर्न' ने बढ़ाई शंकाएं, जिम्मेदारी तय करने की मांग तेज

(जीएनएस)। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर रविवार को हुई भगदड़ की घटना ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस छेड़ दी है। यात्रियों की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दे एक बार फिर केंद्र में आ गए हैं। घटना के अगले ही दिन हालात सामान्य भले दिखे हों, लेकिन इसके पीछे छिपे सवाल और विवाद अब भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ा विवाद उस समय खड़ा हुआ जब Western Railway के जनरल मैनेजर Ramashray Pandey ने घटनास्थल का दौरा कर लाठीचार्ज की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया।

जनरल मैनेजर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यात्रियों पर किसी भी प्रकार का लाठीचार्ज नहीं किया गया। उनके अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में जो दृश्य दिख रहे हैं, उनमें Railway Protection Force के जवान लाठियां जरूर चला रहे हैं, लेकिन वह यात्रियों पर नहीं, बल्कि स्टेशन की फेंसिंग पर मार रहे थे, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को "गलत नैरेटिव" बताते हुए कहा कि तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है।

हालांकि, रेलवे प्रशासन के इस बयान ने विवाद को शांत करने के बजाय और हवा दे दी है। प्रत्यक्षदर्शियों और यात्रियों का कहना है कि स्थिति इतनी भयावह थी कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागना पड़ा। कई यात्रियों ने आरोप लगाया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया गया, जिससे अफरा-तफरी और बढ़ गई। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि यदि लाठीचार्ज नहीं हुआ, तो फिर भीड़ अचानक इतनी बेकाबू कैसे हो गई?

घटना के मूल में भीड़ प्रबंधन की विफलता को प्रमुख कारण माना जा रहा है। यात्रियों का आरोप है कि स्टेशन पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। न तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उचित बैरिकेडिंग थी और न ही यात्रियों को मार्गदर्शन देने के लिए पर्याप्त स्टाफ मौजूद था। पीने के पानी की कमी, टिकट काउंटरों पर अव्यवस्था और प्लेटफॉर्म पर अनियंत्रित भीड़ ने मिलकर हालात को विस्फोटक बना दिया। ऐसे में छोटी सी चूक भी बड़े हादसे का रूप ले सकती थी।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे देश में, जहां रेलवे रोजाना करोड़ों लोगों की आवाजाही का माध्यम है, वहां भीड़ प्रबंधन केवल एक औपचारिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक अत्यंत संवेदनशील जिम्मेदारी है। त्योहारों, छुट्टियों या विशेष ट्रेनों के दौरान यह जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उधना स्टेशन की घटना इस बात का संकेत है कि जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में कहीं न कहीं गंभीर कमी है। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू है—जवाबदेही का अभाव। जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो अक्सर जिम्मेदारी तय करने के बजाय बयानबाजी शुरू हो जाती है। प्रशासन अपनी छवि बचाने की कोशिश करता है, जबकि आम जनता जवाब चाहती है। उधना स्टेशन की घटना में भी यही देखने को मिल रहा है। एक तरफ रेलवे अधिकारी इसे सामान्य घटना बताने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यात्री इसे अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मान रहे हैं।

सोशल मीडिया ने इस पूरे घटनाक्रम को और भी संवेदनशील बना दिया है। वायरल वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लोगों के बीच तेजी से फैल रहे हैं, जिससे प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर साफ नजर आ रहा है। यही कारण है कि यह मामला अब केवल एक स्थानीय घटना नहीं रह गया, बल्कि पूरे देश में रेलवे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। घटना के अगले दिन जब उधना स्टेशन पर सन्नाटा और सामान्य स्थिति देखने को मिली, तो यह एक तरह से राहत की बात जरूर थी, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। असली चुनौती यह है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए। इसके लिए केवल बयान देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि ठोस और प्रभावी कदम उठाने होंगे। विशेषज्ञ सुझाव दे रहे हैं कि रेलवे को अपने भीड़ प्रबंधन तंत्र को आधुनिक तकनीकों से लैस करना चाहिए। रियल-टाइम मॉनिटरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भीड़ विश्लेषण, बेहतर सिग्नलिंग और यात्रियों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जैसी व्यवस्थाएं लागू की जा सकती हैं। इसके अलावा, स्टाफ की संख्या बढ़ाना, नियमित प्रशिक्षण और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए विशेष ड्रिल भी जरूरी हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। रेलवे केवल एक परिवहन सेवा नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों की जीवनरेखा है। ऐसे में हर छोटी-बड़ी चूक का असर सीधे लोगों की जिंदगी पर पड़ता है।

पूर्व सैनिक ने चमत्कार कर दिखाया: 138 डिग्रियां प्राप्त करके शिक्षा के क्षेत्र में एक अनूठा रिकॉर्ड

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। शिक्षा और कला की कोई उम्र सीमा या बंधन नहीं होता। राजस्थान के एक पूर्व सैनिक ने इसे साबित कर दिया है। इतना ही नहीं, वे आलसी लोगों के लिए प्रेरणा भी बन गए हैं। राजस्थान के इस पूर्व सैनिक ने 138 डिग्रियां, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र हासिल किए हैं। यह आम लोगों की एक से पांच योग्यताओं की तुलना में कहीं अधिक है। झुंझुन जिले के निवासी दशरथ सिंह को हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) के दीक्षांत समारोह में वैदिक अध्ययन में मास्टर डिग्री विशिष्टता के साथ पूरी करने पर उनकी नवीनतम योग्यता से सम्मानित किया गया।

55 वर्षीय दशरथ सिंह का दावा है कि उन्होंने 11 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। इनमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज रिकॉर्ड शामिल हैं। ये सभी रिकॉर्ड शिक्षा के क्षेत्र में हैं। हालांकि पीटीआई को इन रिकॉर्ड्स की तस्वीरें मिली हैं, लेकिन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। दशरथ सिंह कहते हैं, "मेरे परिवार में कोई भी शिक्षित नहीं था, फिर भी मैंने एक छोटे से गांव के स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की। सरकारी स्कूल से 10वीं कक्षा पास करने के बाद, आर्थिक तंगी के कारण कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करना एक दूर का सपना लगता था।" उनका जन्म नवलगढ़ तालुका के खिरोद गांव में हुआ था, जो अपने युवाओं को सशस्त्र बलों में भेजने के लिए जाना जाता है।

उन्होंने 1988 में भारतीय सेना में प्रवेश किया। पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा अन्य स्थानों पर गैर-कमीशन अधिकारी के रूप में 16 वर्षों तक सेवा करने के बाद वे 2004 में सेना से सेवानिवृत्त हुए। किसान परिवार से आने वाले दशरथ सिंह कहते हैं कि सेवा के दौरान उन्हें हमेशा लगता था कि उनकी शिक्षा "अधूरी" है। इसी भावना ने उन्हें सेवा के दौरान भी अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। इसलिए जब भी उन्हें दो महीने की वार्षिक छुट्टी मिलती, वे उस छुट्टी का उपयोग पढ़ाई के लिए करते और सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने अपने शौक को पूरे जोश के साथ आगे बढ़ाया।

"मैंने सबसे पहले वाणिज्य में स्नातक की डिग्री पूरी की, फिर नियमित छात्र के रूप में एलएलबी, एलएलएम, बीजेएमसी और बी.एड की पढ़ाई की। इसके साथ ही मैंने इग्नू, जैन विश्व भारती संस्था और निजी विश्वविद्यालयों से अन्य योग्यताएं भी हासिल कीं," दशरथ सिंह कहते हैं। अब तक उन्होंने तीन पीएचडी, सात स्नातक डिग्री, 46 स्नातकोत्तर डिग्री, 23 डिप्लोमा, सैन्य अध्ययन से संबंधित सात डिग्री और विभिन्न विषयों में 52 प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं।

लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद का सफर सिर्फ डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं था। सेवानिवृत्ति के बाद, मैंने सैनिकों के कल्याण में योगदान देने की आवश्यकता महसूस की। मैंने कानून की डिग्री प्राप्त की और वकालत शुरू कर दी। दशरथ सिंह बताते हैं, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद सेना की सतपा शक्ति कमान में कानूनी सलाहकार का पद संभाला और सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों से संबंधित मामलों को संभाला।

यह एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति की कहानी है। अगर कोई अश्वेत व्यक्ति ठान ले तो क्या नहीं कर सकता?

एसआईआर के खिलाफ आवाज: बुद्धिजीवी-वकीलों ने मतदाता सूची समीक्षा को तत्काल समाप्त करने की मांग की

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। इन दिनों देश के विभिन्न हिस्सों में नगर निगमों से लेकर विधानसभाओं तक के चुनाव चल रहे हैं और चल रही मतदाता सूची समीक्षा (एसआईआर) का भी विरोध हो रहा है। ऐसे में बुद्धिजीवियों, वकीलों, छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक समूह ने मतदाता सूची समीक्षा (एसआईआर) को तत्काल समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने इसे "नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध" बताया है और पुरानी मतदाता सूचियों को जारी रखने और उनके आधार पर चुनाव कराने का आह्वान किया है।

आयोजकों द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह मांग शनिवार को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मानवाधिकार संगठन "जन हस्तक्ष" द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में रखी गई थी। संगोष्ठी में पूर्व चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर बद्री रैना, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की अध्यक्ष संगीता बरुआ पिशारोटी सहित अन्य उपस्थित थे। संगोष्ठी में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया।

पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को तत्काल रोका जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, जिन लोगों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, उनकी अपीलों पर तुरंत फैसला किया जाना चाहिए। उन्हें मतदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। या फिर सभी के लिए मतदान के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए 2025 की अद्यतन मतदाता सूची का उपयोग किया जाना चाहिए।

प्रस्ताव में कहा गया है कि अन्यथा पश्चिम बंगाल विधानसभा के चल रहे चुनाव निरर्थक हो जाएंगे। एसआईआर प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग की भूमिका केवल मतदाता सूची में नाम शामिल करना है। वह नागरिकता दस्तावेजों की मांग या सत्यापन नहीं कर सकता। नागरिकता का निर्धारण गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। इस संगोष्ठी के संयोजक जेएनयू के विकास बाजपेयी और सह-संयोजक पत्रकार अनिल दुबे थे।

उधना स्टेशन पर भीड़ का विस्फोट: ट्रेनों की कमी से मचा हाहाकार, 20 हजार यात्रियों ने बिगाड़े हालात

(जीएनएस)। सूरत। शहर के उधना रेलवे स्टेशन पर रविवार को जो नजारा देखने को मिला, उसने एक बार फिर देश के व्यस्त रेलवे नेटवर्क और प्रवासी यात्रियों की चुनौतियों को उजागर कर दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले यात्रियों की अचानक उमड़ी भीड़ ने स्टेशन को मानो ठहर सा दिया। करीब 20 हजार यात्रियों के एक साथ पहुंचने से प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जहां लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने की जद्दोजहद में घंटों तक जूझते रहे। स्थिति इतनी विकट हो गई कि यात्रियों के बीच धक्का-मुक्की और अव्यवस्था आम बात बन गई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार विकास परिषद के पदाधिकारियों ने पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक रामाश्रय पांडे से मुलाकात कर स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया। परिषद ने स्पष्ट किया कि यह समस्या अचानक नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही व्यवस्थागत कमी का परिणाम है। प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों की लगातार बढ़ती संख्या के मुकाबले ट्रेनों की उपलब्धता बेहद कम है, जिससे हर बार त्योहारों, छुट्टियों या विशेष अवसरों पर ऐसी भीड़ का विस्फोट होता है। रेलवे प्रशासन ने यह स्वीकार किया कि यात्रियों की संख्या को देखते हुए पहले से कुछ तैयारियां की गई थीं, लेकिन अचानक उमड़ी इस भीड़ के सामने वे नाकाफी साबित हुईं। हालात को संभालने के लिए आनन-फानन में एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था भी की गई, लेकिन सूचना के अभाव और अफवाहों के चलते स्थिति और बिगड़ गई। बड़ी संख्या में यात्रियों को यह भ्रम हो गया कि इस अनारक्षित स्पेशल ट्रेन में आसानी से सीट मिल जाएगी, जिसके कारण भीड़ एक ही स्थान पर केंद्रित हो गई और अव्यवस्था चरम पर पहुंच गई।

इस घटना ने एक और गंभीर तथ्य को उजागर किया—बिहार जाने वाली नियमित ट्रेनों में अगले दो महीनों तक सीटों की उपलब्धता लगभग समाप्त हो चुकी है। ऐसे में यात्रियों के पास सीमित विकल्प बचते हैं, जिससे वे किसी भी उपलब्ध ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों। यह स्थिति न केवल यात्रियों की असुविधा बढ़ाती है, बल्कि रेलवे प्रशासन के लिए भी भीड़ प्रबंधन को एक बड़ी चुनौती बना देती है। बिहार विकास परिषद ने इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से केंद्रीय स्तर पर मांग उठाई है कि सूरत जैसे औद्योगिक शहरों से बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए नियमित ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। परिषद का कहना है कि सूरत में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर रहते हैं, जो समय-समय पर अपने गृह राज्यों की यात्रा करते हैं, लेकिन ट्रेनों की सीमित संख्या के कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समस्या के स्थायी समाधान के लिए परिषद ने कई व्यावहारिक सुझाव भी दिए हैं। इनमें ट्रेन संख्या 20933 उधना-दानापुर एक्सप्रेस को प्रतिदिन जयनगर तक नियमित रूप से चलाने, उधना से भागलपुर के लिए नई दैनिक ट्रेन शुरू करने और उधना से कोडरमा वाया गया के लिए प्रतिदिन ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग शामिल है।

सोना वायदा में 763 रुपये और चांदी वायदा में 4741 रुपये की नरमी: क्रूड ऑयल वायदा 475 रुपये तेज

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 194758.01 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 22482.58 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 172275.43 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2617.28 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 14946.56 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा सत्र के आरंभ में 153158 रुपये के भाव पर खूलकर, 153880 रुपये के दिन के उच्च और 152799 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 154609 रुपये के पिछले बंद के सामने 763 रुपये या 0.49 फीसदी लुढ़ककर 153846 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी अप्रैल वायदा 653 रुपये या 0.53 फीसदी घटकर 122680 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-पेटल अप्रैल वायदा 71 रुपये या 0.46 फीसदी घटकर 15375 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। सोना-मिनी मई वायदा 151982 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 152450 रुपये और नीचे में 151256 रुपये पर पहुंचकर, 758 रुपये या 0.49 फीसदी घटकर 152418 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-टेन अप्रैल वायदा प्रति 10 ग्राम 152232 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 152665 रुपये और नीचे में 151576 रुपये पर पहुंचकर, 153398 रुपये के पिछले बंद के सामने 781 रुपये या 0.51 फीसदी घटकर 152617 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा 253453 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 254089 रुपये और नीचे में 250730 रुपये पर पहुंचकर, 257142 रुपये के पिछले बंद के सामने 4741 रुपये या 1.84 फीसदी घटकर 252401 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 4113 रुपये या 1.59 फीसदी औंधकर 254420 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 4150 रुपये या 1.61 फीसदी घटकर 254389 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

मेटल वर्ग में 2307.60 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा अप्रैल वायदा 3.6 रुपये या 0.28 फीसदी औंधकर 1269.3 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता अप्रैल वायदा 2.35 रुपये या 0.69 फीसदी की तेजी के संग 341.45 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इसके सामने एल्यूमीनियम अप्रैल वायदा 1.95 रुपये या 0.54 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 365.4 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा अप्रैल वायदा 25 पैसे या 0.13 फीसदी घटकर 194.85 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 4888.77 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल अप्रैल वायदा 8077 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 8388 रुपये और नीचे में 8077 रुपये पर पहुंचकर, 475 रुपये या 6.12 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 8242 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी अप्रैल वायदा 466 रुपये या 6 फीसदी बढ़कर 8234 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 252.3 रुपये के भाव पर खूलकर, 255.8 रुपये के दिन के उच्च और 250.5 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 250.2 रुपये के पिछले बंद के सामने 4.5 रुपये या 1.8 फीसदी की बढ़त के साथ 254.7 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी अप्रैल वायदा 4.6 रुपये या 1.84 फीसदी बढ़कर 254.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 22482.58 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 172275.43 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 14946.56 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल अप्रैल वायदा 988.3 रुपये पर खूलकर, 90 पैसे या 0.09 फीसदी टूटकर 991 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 7728.55 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 7218.00 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 1650.14 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 364.41 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 20.83 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 263.45 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 3670.94 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1188.14 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 1.50 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.14 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9739 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 60588 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 26992 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 373265 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 61804 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 7734 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 24182 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 87178 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 14989 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 39621 लोट के स्तर पर था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मई 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 89.7 रुपये की बढ़त के साथ 235.6 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 255 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 95 पैसे के सुधार के साथ 5.25 रुपये हुआ।

सोना अप्रैल 160000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 222.5 रुपये की गिरावट के साथ 760 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 260000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2635.5 रुपये की गिरावट के साथ 2680.5 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.69 रुपये की गिरावट के साथ 1.42 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 335 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.26 रुपये की गिरावट के साथ 6.99 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मई 7000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 106.9 रुपये की गिरावट के साथ 185.2 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 250 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.65 रुपये की गिरावट के साथ 3.5 रुपये हुआ। सोना अप्रैल 145000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 29 रुपये की बढ़त के साथ 444 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 250000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 952.5 रुपये की बढ़त के साथ 4256.5 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1260 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.07 रुपये की गिरावट के साथ 11.6 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3.14 रुपये की बढ़त के साथ 10.4 रुपये हुआ।